

संक्षिप्त समाचार

पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने की मुख्यमंत्री साय से मुलाकात



रायपुर। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने बीतों रात मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान समाचारियक विषयों पर बातचीत हुई। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। इस मोक्ष पर मुख्यमंत्री साय ने उन्हें शाल और बस्तर को कलाकृति देकर सम्मानित किया। प्रभात झा का छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की मीटिंग से गहरा नात रहा है। अब अधिभासित मध्य प्रदेश के भाजपा मीटिंग प्रभारी रख चुके हैं। बात में मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व का भी विवेहन कर चुके हैं। भाजपा के मुख्यपत्र कमल सन्देश के संपादक हें झा से मुख्यमंत्री साय ने कई पुराने अवसरों की स्मृतियां साजा की।

एसीबी की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपये रिश्वत लेते रहे हथ पकड़ाया एसडीओ

खैरागढ़। जिले में एसीबी की टीम ने गुरुवार



को बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने लोक स्वास्थ्य वाक्तिकी छुईखदान में छापामार कार्रवाई कर अधिकारी को निश्चित लेते रहे हथ गिरफतार किया है। टेकेदार से बिल पास करवाने के नाम पर अधिकारी पैसे की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने डेंड लाख रुपये की रिश्वत के साथ एसडीओ राजेश मदावे को रोनी हथ पकड़ लिया। प्रार्थी टेकेदार प्रवीन कुमार तिवारी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। प्रार्थी टेकेदार के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से टेंडर के बिल को पास करने के बिंदु में पैसे की मांग करता था। अंतः परेशन होकर प्रार्थी ने एसीबी में शिकायत की। इसके बाद एसीबी ने लोक स्वास्थ्य वाक्तिकी छुईखदान पहुंच कर छापामार कार्रवाई करते हुए एसडीओ को गिरफतार कर लिया।

कांग्रेस ने गृहमंत्री शर्मा के खिलाफ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की शिकायत

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारियों



ने गृहमंत्री विजय शर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्य

निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है। कांग्रेस

ने दावा किया है कि गृहमंत्री विजय शर्मा ने अपने नेतृत्व में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की है। इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने शिकायत पत्र में कहा है कि भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में गृहमंत्री विजय शर्मा ने अपने नेतृत्व में आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए नाप्रतिपक्ष डाँ। चरणदास महंत के पदाधिकारियों

ने गृहमंत्री विजय शर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्य

निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है। कांग्रेस

ने गृहमंत्री विजय शर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की मांग की गई है।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा का एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा का गुरुवार को नई दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। जहां एनएसयूआई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और ढोल नगाड़े, आतिशबाजी के साथ जोरावर स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा राम मंदिर पहुंचकर रामलाल का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं पूजा कर प्रदेश कार्यालय राजीव भवन पहुंचे, जहां पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राजीव भवन में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश एवं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पाठे मौजूद थे।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा ने कहा, आज में 12 वर्षों से छात्र राजनीति में हूं। आज कॉलेज के सचिव से लेकर राष्ट्रीय सचिव का सफर बेहद रोमांचक रहा। बहुत सारी अड़चने आई। आपके एवं अधिकारी से गृहमंत्री विजय शर्मा को बहुत सारी बाधाएँ आई हैं। एसीबी में गृहमंत्री विजय शर्मा को मांग की है। कि इस विरोध प्रदर्शन का परमिशन नहीं दिया गया। कांग्रेस नेतृत्वों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि गृहमंत्री विजय शर्मा के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की कार्रवाई की जाए। साथ ही गृहमंत्री विजय शर्मा को मांग की है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारियों

ने गृहमंत्री विजय शर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की मांग की गई है।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा को बर्खास्त करने की मांग की गई है। आयोग ने कांक्रे

लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है। आयोग ने कांक्रे

लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री शशि रंजन को सामान्य प्रेश्वक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी डॉ. समित शर्मा को सामान्य प्रेश्वक और भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए एम.राकेश चंद्र कलासागर को पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी डॉ. एमटी रेजु को सामान्य प्रक्षक, भारतीय पुलिस प्रेश्वक की नियुक्ति की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के

अमेरिका, यूरोप के निशाने पर क्यों हैं मोदी?

अजय सेतिया

अप्रेल और मई में होने वाले भारत की लोकसभा के चुनावों में अमेरिका, यूरोप और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की दिलचस्पी 2014 के चुनावों से भी ज्यादा है। 2014 में भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भारत के विपक्षी नेताओं ने दुनिया भर के मीडिया में उनके खिलाफ अभियान चलाया था। उनके प्रधानमंत्री चुने जाने बाद भी यह अभियान चलता रहा है। पिछले कुछ सालों में विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी अपने विदेशी दौरों में मोदी सरकार पर संविधान और लोकतंत्र को कुचलने और अपने विरोधियों के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय संसद से पारित कई बिलों को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गई, और सुप्रीमकोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठाए जाते रहे।

भारत के विपक्ष के उकसाव पर विदेश माड़या न भी नागरिकता संशोधन कानून और कृषि कानूनों की गलत व्याख्या करने से परहेज नहीं किया। कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने को कोशिश की गई, जिसका पाकिस्तान ने लाभ उठा कर इसे संयुक्त राष्ट्र में उठाया। राहुल गांधी को जब मानवानि के एक केस में दो साल की सजा हुई और सुप्रीमकोर्ट के पूर्व के फैसले और जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई, तो उसकी भी विदेशी मीडिया और विदेशी सरकारों ने गलत व्याख्या की। राहुल गांधी ने देश से बाहर जाकर कहा कि उन्होंने संसद में नरेंद्र मोदी से उद्योगपति गौतम अडानी से उनके रिश्तों पर सवाल पूछे थे, इसलिए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। अमेरिकी सरकार ने तथ्यों की जानकारी लेने के बजाए राहुल गांधी के बयान को ही सच मान कर भारत के लोकतंत्र पर चिंता प्रकट की। यह कहा गया कि विपक्ष की आवाज को दबाने के

16



चलाया था। उनके प्रधानमंत्री चुने जाने बाद भी यह अभियान चलता रहा है। पिछले कुछ सालों में विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी अपने विदेशी दौरों में मोदी सरकार पर सर्विधान और लोकतंत्र को कुचलने और अपने विरोधियों के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय संसद से पारित कई बिलों को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गई, और सुप्रीमकोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठाए जाते रहे।

भारत के विपक्ष के उक्सावे पर विदेशी मीडिया ने भी नागरिकता संशोधन कानून और कृषि कानूनों की गलत व्याख्या करने से परहेज नहीं किया। कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, जिसका पाकिस्तान ने लाभ उठा कर इसे संयुक्त राष्ट्र में उठाया। राहुल गांधी को जब मानहनि के एक केस में दो साल की सजा हुई और सुप्रीमकोर्ट के पूर्व के फैसले और जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई, तो उसकी भी विदेशी मीडिया और विदेशी सरकारों ने गलत व्याख्या की। राहुल गांधी ने देश से बाहर जाकर कहा कि उन्होंने संसद में नरेंद्र मोदी से उद्योगपति गैरतम अडानी से उनके रिश्तों पर सवाल पूछे थे, इसलिए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। अमेरिकी सरकार ने तथ्यों की जानकारी लेने के बजाए राहुल गांधी के बयान को ही सच मान कर भारत के लोकतंत्र पर चिंता प्रकट की। यह कहा गया कि विपक्ष की आवाज को दबाने के भारतीय लोकतंत्र पर चिंता प्रकट की है। स्वाभाविक है कि यह भारत के अंतरिक मामलों में बेवजह का दखल है, जिस पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इन दोनों देशों के दूतावास के अधिकारियों को तलब करके न सिर्फ नाराजगी का इजहार किया, बल्कि भारत के अंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की नसीहत भी दी। लेकिन अमेरिका और जर्मनी के बयान राहुल गांधी के पिछले साल ब्रिटेन में दिए गए बयान की तज पर ही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि खुद को लोकतंत्र का झंडाबरदार समझने वाले अमेरिका और यूरोपियन देशों को भारत में लोकतंत्र पर मंड़ा रहे खतरे पर आँख मूँदे नहीं रहना चाहिए। अपनी भारत जोड़े यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अमेरिका और ब्रिटेन में दिए भाषणों में मोदी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कही थी। राहुल गांधी के अमेरिका और यूरोप के दौरे के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अरविन्द केजरीवाल को विपक्षी गठबंधन में शामिल किया। जिस तरह अमेरिका ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर सवाल खड़ा किया था, ठीक उसी तरह अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, जबकि उनसे पूछताछ के लिए रिमांड दिया गया है। इसलिए पत्रकार का सवाल ही राजनीति से प्रेरित और प्रायोजित था, और जवाब उससे भी अधिक प्रायोजित और राजनीति से प्रेरित था। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ने पहले से लिखा हुआ जवाब पढ़ने हुए कहा कि भारत या जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, वहाँ सभी के नागरिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के इस बयान को भारत में एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया गया। क्या यह संयोग है कि अरविन्द केजरीवाल के बकील अधिकार मनु संघवी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार नागरिक अधिकारों का हवाला दिया था। विपक्ष के लगभग सभी नेताओं और केजरीवाल के यहाँ तक कि जब केजरीवाल खुद राहत पाने के लिए हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी थी। गिरफ्तारी के बाद भी वह जांच में ईडी को सहयोग नहीं दे रहे, उन्होंने ईडी को अपने फोन और अन्य इलेक्ट्रोनिक डिवाइस के पासवर्ड देने से इंकार कर दिया है। चुनावों से ठीक पहले विदेशों से नरेंद्र मोदी सरकार पर अचानक हमले तेज नहीं हुए हैं। इसकी पटकथा पिछले दो साल से लिखी जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईंडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे ज्यादा फर्डिंग करने वाले जार्ज सोरोस ने कुछ महीन पहले कहा था कि भारत में लोकतंत्र तब पुनर्जीवित होगा, जब नरेंद्र मोदी चुनाव होरेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़े यात्रा के समय जार्ज सोरोस का एक प्रतिनिधि उनसे मिलने भी पहुंचे था, जिसकी राहुल गांधी के साथ चलते हुए तस्वीर वायरल हुई थी। राहुल गांधी जब भारत जोड़े यात्राओं के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन गए थे, तो उनके सारे कार्यक्रमों का आयोजन जिन एनजीओ ने किया था, उनको जार्ज सोरोस फर्डिंग करते हैं। जार्ज सोरोस ने मोदी को चुनावों में हराने के लिए असीमित पैसा खर्च करने का एलान किया हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईंडेन की पार्टी को सबसे ज्यादा फर्डिंग जार्ज सोरोस ही करते हैं, और वह अमेरिका की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका का बाईंडेन प्रशासन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहता। खबर यह है कि अमेरिका मोदी के मुकाबले लचीले रुख वाला प्रधानमंत्री देखना चाहता है,

मादा सरकार में केसा बदली विदेश नीति

हृषि वा पते

राजनीति में एक दिन भी काफी लबा समय हो सकता है, लेकिन विदेश नीति में एक दशक को भी अक्सर गंभीर मूल्यांकन के लिहाज से पर्याप्त नहीं माना जाता। हालांकि, पिछला दशक इस मामले में अपवाद रहा है। इस दौरान वैश्विक राजनीति में आए बदलावों की प्रकृति तो खास है ही, इनका दायरा भी व्यापक रहा है। ऐसे में भारतीय विदेश नीति में भी बुनियादी बदलाव आना स्वाभाविक है। लेकिन विदेश नीति में आए इन बदलावों पर वैश्विक हालात और समीकरणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत भागीदारी की भी अमिट छाप नजर आती है। याद किया जा सकता है कि मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्हें एक ऐसा क्षत्रिय बताया जा रहा था जिसे विदेशी नीति का कोई अनुभव नहीं था। ‘हिंदू राष्ट्रवादी नेता’ की उनकी छवि को भी खास तौर पर इस्लामी राष्ट्रों के साथ अच्छे रिश्तों की राह में बाधा माना जा रहा था। लेकिन मोदी ‘ईंडिया फर्स्ट’ के मंत्र को केंद्र में रखते हुए एक व्यावहारिक विदेश नीति को अपनाकर विरोधियों और समर्थकों दोनों को चौंकाने में कामयाब रहे। इन दस वर्षों में उन्होंने भारतीय विदेश नीति को ऐसा रूप दिया, जिसके बारे में पहले शायद ही किसी ने कल्पना की हो। पीएम मोदी की अगुआई में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि वैश्विक मंच पर न केवल अहम भूमिका निभाने बल्कि रूल मेकर के रोल में आने की नई दिल्ली की आकांक्षा लगातार मजबूत होती गई। वैश्विक मंच पर मोदी की कूटनीति ने भारतीय आकांक्षाओं को नए पंख दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले दशक तक वैश्विक मामलों में अहम भूमिका की पेशकश तुकराने वाला देश एक ऐसे राष्ट्र में तब्दील हो गया, जो ग्लोबल गवर्नेंस में योगदान करने के लिए हमेशा आगे नजर आता है। पिछले दिनों सोमालिया के पास समुद्री डाकुओं के चंगुल में फंसे एक कर्मशल जहाज को छुड़ाने का भारतीय नौसेना का अभियान इस बात का ताजा सबूत है। मोदी के इस एक दशक के दौरान घरेलू और विदेशी का कृत्रिम विभाजन खत्म हो गया। भारत की मुख्य प्राथमिकता घरेलू मोर्चे पर विकास के जरिए हो रही कायापलट ही रही। भारतीय कूटनीति भी विकास संबंधी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के एक साधन के रूप में संचालित होती रही। इसने बाहरी दुनिया से हमारे संपर्कों को एक खास व्यावहारिक नजरिया दिया जिसके तहत अब विचारधारा के बजाय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई। संबंध राष्ट्रों जरूरतों से तय होने लगे। इसका एक बेहतरीन उदाहरण तब सामने आया, जब यूक्रेन युद्ध के बीच भारत पश्चिमी देशों के साथ करीबी रिश्ता बनाए रखते हुए रूस से अपने विशिष्ट संबंध भी कायम रखने में कामयाब रहा।

अमराका दारता म बाह मराइन का बदाश्त नहा करगा भारत

पांगड़ पांगा

प्रदल का नुमुखनना उत्तरपद प्रबोधनारायण मानसी ने अमरीका को उसी के लहजे में सख्त जवाब देकर भारत ने बता दिया है भारत के अंदरूनी मामलों में किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाशत नहीं किया जाएगा, चाहे वे मित्र देश ही क्यों न हों। कड़ा जवाब देकर भारत ने अमरीका को यह भी समझा दिया कि दोस्ती की आड़ में बांह मरोड़ने का प्रयास दोनों देशों के रिश्तों में दरार डाल सकता है।

ऐसा करने पर भागत-अमरीका के रिश्तों पर फूर्क पड़

ऐसा करने पर भारत-अमेरिका के इश्ता पर फक पड़ सकता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर की गई कुछ टिप्पणियों के विरोध में अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत द्वारा तलब किये जाने पर वाशिंगटन ने दोहराया था कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था मैं किसी निजी राजनयिक बातचीत के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से, हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है, वही मैंने यहां से कहा है कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। यही बात हम निजी तौर पर स्पष्ट कर देंगे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने अमेरिकी दूतावास की कार्यवाहक उपरमुख ग्लोरिया बरबेना को तलब किया था, अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी को अनुचित करार देते हुए कहा था कि उसे अपनी स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गर्व है और वह इन्हें किसी भी प्रकार के अनावश्यक बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अमेरिकी डिस्ट्रोमैट ग्लोरिया बरबेना को तलब किया था। मंत्रालय ने कहा था कि भारत में कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान गलत है। कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि देश एक दूसरे के आंतरिक मसलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अगर दो देश लोकतांत्रिक हों तो इसकी उम्मीद और बढ़



जाता है नहीं तो अव्यवस्था का स्थित बन सकता है। गरतल है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति घोटाले जुड़े धन शोधन मामले में केरीवाल को गिरफ्तार किया है। केरीवाल मुद्दे पर अमेरिका की तरफ से आए दूसरे बय पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के बयान पर भास पहले ही आपत्ति जता चुका है। उसका ताजा बयान अवांछनी है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे पर भारत अमेरिका के साथ ही जर्मनी को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में न्याय प्रणाली स्वतंत्र है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास मिशन के उप्रमुख जॉर्ज एन्जीलर को तलब किया। भारत ने जर्मनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताते हुए अपना कड़ा विरोध दर्ज किया।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल देना हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्रता को कमज़ोर करने के रूप देखते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब भारत ने अमेरिका का सुनने से इंकार कर दिया। इससे पहले अमेरिका निवार खालिस्तानी आतंकी गुरुवंत सिंह पन्हू के मामले में भी भारत अमेरिका को सख्त लहजे में समझाते हुए दर्शा दिया था। भारत विरोधी कार्रवाई को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा जाएगा। भारत की दोस्ती को अमेरिका कमज़ोरी नहीं समझता।

अमेरिका अफसरों ने दो भारतीय नागरिकों पर गुपतवत सह
पन्त्रू की हत्या की विफल साजिश में शामिल होने का आरोप
लगाया था। निखिल गुरुा और एक अनाम सरकारी अधिकारी
पर यह आरोप लगाए थे। अमेरिका का ये भी दावा है कि यहीं
आरोपी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर की प्लानिंग में भी शामिल
थे। इसको लेकर न्याय विभाग ने मैनहैटन अदालत में अभियोग
(आरोप पत्र) दर्ज किया था। भारत ने इस मुद्दे पर करारा जवाब
देते हुए अमेरिका को अपनी जमीन से भारत विरोधी
गतिविधियां संचालित करवाने का आरोप लगाया था।

इसी तरह भारत ने आतंकी हरदाप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाड़ा और अमरीका को कड़ा जवाब दिया था। हालांकि इस मुद्दे पर अमरीका ने सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूटो के निज्जर की हत्या करवाने के आरोपों का खारिज करते हुए करीब दो दर्जन से ज्यादा डिप्लोमट को बाहर का रास्ता दिखाते हुए अपनी बदली हुई विदेश नीति से वाकिफ भी करा दिया था। भारत के ऐसे सख्त रवैये से कनाडा भौचक्का रह गया। टूटो ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत ऐसा रवैया भी अखिलयार कर सकता है।

भारत ने कनाडा पर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया था। भारत पर लगाए निज्जर की हत्या के आरोपों का कनाडा साबित नहीं कर सका। केवल सिक्ख वोट बैंक पाने के लिए कनाड़ा ने भारत पर यह आरोप लगाया था। इसी तरह भारत ने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप को लेकर तुर्की की भी खिचाई की थी। कश्मीर के मुद्दे पर भारत-तुर्कीये एक बार फिर से आमने-सामने आ गए थे। आश्वर्य की बात यह है कि अमरीका की पूरे विश्व में अब कोई नहीं सुन रहा है। इजराइल ने भी अमेरिका को अनसुना करके हमास से युद्धविवारण करने से साफ इंकार कर दिया। इसी तरह यूक्रेन युद्ध के मामले में अमरीका की नीति विफल साबित हुई। फांस ने साफ कह दिया कि वह अमरीका का पिछलगू नहीं बनेगा। हालात यह है कि अमरीका अपना घर संभालने के बजाए दूसरे मुल्कों में टांड अड़ने से बाज नहीं आ रहा है।

फिलीपीन के बहाने परिचम को व्यापक संदेश

ગાંધી જાળે

दाक्षिण बान सागर ने कलानीन के द्वारा प्राप्त पर्याप्त चीन के आक्रामक रूख से भारत को अरुणाचल प्रदेश में अपनी संप्रभुता पर चीन के अतिक्रमण के खिलाफ पलटवार करने का अवसर मिला है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा चीनी डेवलपर बाइटडास को सोशल मीडिया सेवा टिकटॉक पर प्रतिबंध को मंजूरी देने से निराश बीजिंग अचानक अपने राष्ट्रवादी रुख के प्रति संवेदनशील हो गया है और पड़ोस में अपने क्षेत्रीय द्वारों के प्रति कठोर रवेया अपना रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर दावा जाताने के तुरंत बाद चीन दक्षिण चीन सागर में स्थित स्प्रैटली द्वीप समूह में फिलीपीन की संप्रभुता को कमज़ोर करने के अपने मंसूबों को लेकर काफी आक्रोश में है।

चीन की इस नई आक्रामकता का भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने खुला विरोध किया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के तीन देशों के दौरे पर थे। विगत 26 मार्च को मनीला की यात्रा के दौरान उन्होंने दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर फिलीपीन के दावों के बारे में उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के प्रति भारत के समर्थन को दृढ़ाया से दोहराया। उन्होंने कहा कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन (यूएनसीएलओएस) को समुद्र का संविधान माना गया है और सभी देशों से आग्रह किया

गया है कि वे इसका अक्षरशः एवं भावों में पूरी तरह से पालन करें।

दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर करीब से नज़र डालते हुए अमेरिकी उप रक्षा मंत्री ने मई, 2015 में सीनेट की बैठक में पुष्टि की कि वियतनाम ने 48 चौकियां स्थापित की हैं, फिलीपीन ने आठ, मलयेशिया ने पांच और ताइवान ने स्ट्रैटली द्वीप समूह में एक चौकी स्थापित की है। छोटे पैमाने पर, वियतनाम और फिलीपीन ने दशकों तक द्वीप निर्माण जारी रखा। चीन बदलती जमीनी हकीकत के प्रति देर से जागा, लेकिन उसने अभूतपूर्व पैमाने पर द्वीप निर्माण शुरू किया। वर्ष 2014 से 2016 के बीच चीन ने पूरे इतिहास में अन्य सभी देशों द्वारा निर्मित द्वीपों की तुलना में सबसे ज्यादा



नए द्वीपों का निर्माण किया और अपने सैन्य उपकरण भी तैनात किए। विशेषज्ञों ने दक्षिण चीन सागर में चीनी कार्रवाई को धीरे-धीरे नष्ट करने की रणनीति बताया है। दक्षिण चीन सागर में और अधिक गिरावट से बचने के लिए जुलाई 2016 में यूएनसीएलओएस के तहत गठित मध्यस्थिता न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों के खिलाफ फैसला सुनाया। हालांकि चीन और ताइवान, दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे न्यायाधिकरण को नहीं मानते हैं और इस मामले को

आक्रामक एकपक्षवाद को रोकने के लिए भारत हिंद-प्रशांत स्तर पर सहकारी बहुपक्षवाद को कायम कर रहा है।

क्षेत्रीय सहयोग में आसियान केंद्रीयता का समर्थन करके भारत ने इस क्षेत्र में न सिर्फ आर्थिक, बल्कि रणनीतिक संबंध बनाने के लिए अपनी एकट ईस्ट नीति को पुनर्जीवित किया है। नई दिल्ली आसियान सदस्यों को एक ऐसे संभावित समूह के रूप में देखती है, जो सामाजिक रूप से बीजिंग पर नियम आधारित उदार

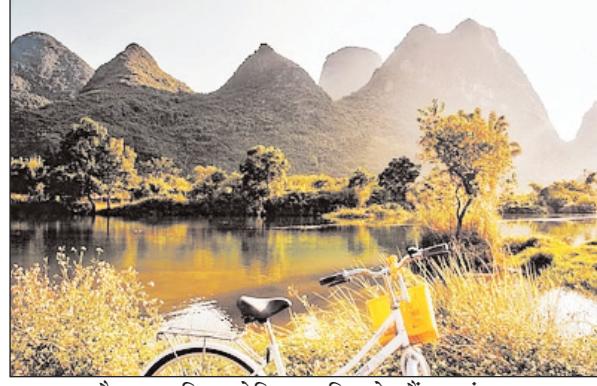
अन्य दावेदारों के साथ द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। जनवरी, 2022 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दक्षिण चीन सागर में चीनी दावे को गैर-कानूनी बताया।

दक्षिण चीन सागर वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सालाना 33.7 खरब डॉलर मूल्य का व्यापारिक सामान इससे होकर गुजरता है। चीन के लिए इस क्षेत्र के महत्व को कोई भी समझ सकता है, क्योंकि उसकी 80 प्रतिशत ऊर्जा और देश के कुल व्यापार का अनुमानित 39.5 प्रतिशत दक्षिण चीन सागर से होकर ही गुजरता है। यह क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस भंडार से सम्बद्ध है। चीनी भूवैज्ञानिक संसाधन और खनन मंत्रालय के अनुसार, दक्षिण चीन सागर में 17.7 अरब बैरल कच्चा तेल हो सकता है, जो तेल समृद्ध क्षुरैत के 13 अरब बैरल के भंडार से बड़ा है। ऐसे उच्च महत्व वाले क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार द्वारा अन्य देशों की जल संप्रभुता के उल्लंघन और द्वीपों पर क्षेत्रीय दावे का न सिर्फ भारत ने विरोध किया है, बल्कि फिलीपीन, वियतनाम और इंडोनेशिया सहित कई अन्य सामूहिक रूप से बांगन पर नियम जारीरत उदार व्यवस्था का पालन करने के लिए दबाव डाल सकते हैं, जो चीन के क्षेत्रीय अलगाव का कारण बन सकता है। अपनी बदली हुई मानसिकता के तहत भारत ने फिलीपीन के साथ रणनीतिक रूप से खुद को जोड़ा है। भारत ने फिलीपीन को परमाणु-सक्षम सुपरसानिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें बेचने का फैसला किया, जो भारत-रूस सहयोग का एक उत्पाद है। भारत ने वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ अपनी रणनीतिक निकटता को भी प्राथमिकता दी है। लगता है कि भारत ने बींजिंग का प्रतिकार करने के लिए एक्ट इस्ट पॉलिसी के ढांचे में उभरती शक्ति कूटनीति को व्यक्त किया है। भारत की उभरती शक्ति कूटनीति हिंद-प्रशांत ढांचे के तहत परिकल्पित वैश्विक रणनीतिक दृष्टि से बेहतर ढंग से मेल खाती है। इस क्षेत्र में कई उभरती हुई शक्तियां हैं, जो हिंद-प्रशांत समूह के भीतर एक छोटा समूह बनाने में सक्षम हैं, और चीन को प्रभावी ढंग से निर्यति कर सकती हैं। एशिया की उभरती शक्तियों में लगातार बढ़ते चीन-अमेरिका विवाद को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता है।

गाजा पट्टी में युद्ध और मानवीय पीड़ा पर विराम की जरूरत

प्राचीन और प्राचीनी

सत्युदारा उत्तरदाता भारपूर न होगा। पट्टी न उद्धव जार मानवावधार नाम के लिए, जोकाल उद्धवप्राप्ति लागू किए जाने और तमाम बन्धकों की तत्काल व बिना शर्त रिहाई की मांग करने वाला एक नया प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव, 11 मार्च को शुरू हुए रमजान के महीने की करुण एवं मानवीय पुकार है, साथ ही, इजराइल पर हमलों के दौरान बन्धक बनाए लोगों में से शेष 130 लोगों को रिहा किए जाने की मांग है। हमास एवं इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को विराम देकर, शांति का उजाला करने, अभय का वातावरण, शुभ की कामना और मंगल का फैलाव करने के लिये को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दृढ़ता से शांति प्रयास एवं युद्ध विराम को लागू करना ही चाहिए। मनुष्य के भयभीत मन को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति देनी चाहिए। इन दोनों देशों को अभय बनकर विश्व को निर्भय बनाना चाहिए। निश्चय ही यह किसी एक देश या दूसरे देश की जीत नहीं बल्कि समूची मानव-जाति की जीत होगी। यह समय की नजाकत को देखते हुए, जरूरी है और इस जरूरत को महसूस करते हुए दोनों देशों को अपनी-अपनी सेनाएं हटाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। गाजा में विश्वाल स्तर पर उपजो आवश्यकताओं और ज़रूरतमन्द आबादी तक मानवीय सहायता पहुँचाएं जाने की भी जरूरत है, क्योंकि वहां के लोग भुखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं। छह महीने से जारी इस भयंकर जंग के दौरान यह पहला मौका है, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्धविराम का प्रस्ताव पारित किया है। यह इसलिए संभव हुआ कि अमेरिका ने इसे बीटो करने से परहेज किया। निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव विश्व जनमत से उपजे दबाव की अभिव्यक्ति है। बड़े शक्तिसम्पन्न राष्ट्रों को इस युद्ध विराम देने के प्रस्ताव को बल देना चाहिए और इसे लागू करने के प्रयास करने चाहिए। पिछले सात अक्टूबर को हमास की ओर से किए गए आतंकी हमले के खिलाफ जब इजराइल ने कार्वाई की बात कही तो अमेरिका और भारत समेत तमाम देशों की सहानुभूति उसके साथ थी। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से गाजा में हवाई हमले शुरू किए और वहां से आम लोगों के हताहत होने की खबरें आने लगीं, उसके बाद यह आवाज तेज होती गई कि इजराइल को अपने अधियान का स्वरूप बदलना चाहिए। अब तक गाजा में करीब 32 हजार लोगों के मरे जाने की खबरें हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। भारत हमेशा युद्ध-विरोधी रहा है, युद्ध-विराम की उसकी कोशिशें निरन्तर चलती रही हैं। किसी भी देश में यह भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा है। भारत ने उचित ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यह भी बता दिया है कि वह सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है और उनसे बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह कर रहा है। निस्संदेह, भारत को मानवता के पक्ष में शांति, युद्ध-विराम और राहत के प्रयासों में जुटे रहना चाहिए। भारत के ऐसे प्रयासों का ही परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्धविराम का ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। गाजा पट्टी में हिंसक टकराव पर विराम लगाने के लिए सुरक्षा परिषद को कई बैठकें हो चुकी हैं, मगर फिलहाल यह सम्भव नहीं हो पाया है। नवम्बर 2023 में एक सप्ताह के लिए लड़ाई रोकी गई थी और गाजा से बंधकों और इजराइल से फलस्तीनी बर्दियों की अदला-बदली हुई थी। मगर, इसके बाद लड़ाई फिर भड़क उठी और इसमें तेजी आई है। गाजा में मृतक संख्या और भूख व कुपोषण से प्रभावित फलस्तीनियों की संख्या निमंत्र बढ़ रही है। इसके मद्देनजर लड़ाई को जल्द से जल्द रोके जाने और मानवीय पीड़ा पर मरहम लगाने की मांग भी प्रबल हो रही है। दुनिया के किसी भी हिस्से में मानवता का इस तरह पीड़ित एवं मर्माहत होना शर्म की बात है। इस शर्म को लगातार होते रहना शक्तिसम्पन्न एवं निर्णायक राष्ट्रों के लिये शर्मनाक ही है। अब एक सार्थक पहल हुई है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए।



1 अप्रैल का दिन ऑडिशा टिकाने हैं जहां आकर आप के लिए बहुत ही खास होता है अपनी छुट्टियों को शानदार बना क्योंकि आज ही के दिन सकते हैं ऐसी ही एक जगह है ऑडिशा राज्य की स्थापना हुई दरिंगबाड़ी जहां को सौर आज थी। खूबसूरती के साथ ऑडिशा हम करें। अपने नृत्य और व्यंजनों के लिए साल 1936 में आज यानी 1 भी बेहद अप्रैल के दिन ऑडिशा को एक मशहूर है। अलग राज्य के रूप में मान्यता यहां कई दी गयी थी, जिसके बाद से हर साल इस दिन को ऑडिशा दिवस

